भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2833

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

रायलसीमा में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना

2833. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और सहायता सहित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वर्ष 2019 से रायलसीमा क्षेत्र में प्रस्तावित, स्वीकृत और कार्यशील इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों की जिला-वार संख्या कितनी है और उक्त परियोजनाओं की प्रकृति तथा इनसे सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से रायलसीमा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए किए गए प्रतिबद्ध और प्राप्त निवेश का ब्यौरा क्या है, तथा इसके साथ स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से रायलसीमा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर, साझा अवसंरचना, कौशल निर्माण सुविधाएं और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का रायलसीमा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को गति देने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने या अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं।

सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक सुविचारित रणनीति अपनाई - जिसकी शुरुआत तैयार उत्पादों के विनिर्माण से हुई, इसके बाद उप-संयोजन, घटकों और अंततः मशीनरी और उपकरण शामिल हुए। साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को समर्थन देने के लिए आवश्यक अवसरंचना के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। पिछले 12 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में काफी विस्तार हुआ है, जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से अवलोकित किया जा सकता है:

#	2014-15	2025-26	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (₹)	~1.9 लाख करोड़	~13.11 लाख करोड़	7 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (₹)	~38 हजार करोड़	~4.24 लाख करोड़	11 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (₹)	~18 हजार करोड़	~6.27 लाख करोड़	33 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (₹)	~15 सौ करोड़	~ 2.59 लाख करोड़	165 गुना वृद्धि

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि संभव हुई है। कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पेक्स)
- भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम।
- भारत में विनिर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश।
- इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति

ये पहलें अखिल भारतीय प्रकृति की हैं और इन्हें देश भर में औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तथापि, विनिर्माण इकाइयों का स्थान उद्योग द्वारा राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाई गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के साथ-साथ वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक विचारों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, जबकि सरकार पूरे भारत में लागू नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करती है, विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और स्थान के संबंध में अंतिम निर्णय उद्योग पर आधारित है।

<u>आंध्र प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं:</u>

आंध्र प्रदेश राज्य में, एमईआईटीवाई की विभिन्न योजनाओं के तहत 89 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई है। विवरण इस प्रकार हैं:

#	जिला	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों की संख्या
1	तिरुपति	54
2	चित्तूर	20
3	वाईएसआर कडप्पा	12
4	विशाखापत्तनम	2
5	कृष्ण	1

<u>(i) सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम</u>

सेमीकंडक्टर के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार ने सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्स सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की स्थापना और भारतीय डिजाइन वाले चिप्स को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने के लिए एक (01) इकाई को मंजूरी दी है। इस सुविधा की उत्पादन क्षमता लगभग 96 मिलियन यूनिट/वर्ष होगी।

(ii) <u>इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)</u>

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को और अधिक गहरा और व्यापक बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसीवर जैसे उप-असेंबली; प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), पैसिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंपोनेंट्स, लिथियम-आयन (ली-आयन) सेल, एनक्लोज़र जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स; इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पूंजीगत उपकरण; तथा उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में (वैश्विक/घरेलू) निवेश आकर्षित करके एक सुदृढ़ कंपोनेंट विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना है।

इस योजना के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर में दो (02) तथा तिरुपति में छह (06) आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

(iii) बड़े पैमाने पर इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गति प्रदान करने और देश में मोबाइल फोन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में दो (02) कंपनियों को अनुमोदित किया गया है।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना

इसके बाद, भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट, एआईओ, सर्वर, आदि) के लिए एक सुदृढ़ घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, आयात निर्भरता को कम करने और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाने के लिए वर्ष 2023 में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 भी शुरू की। इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक (01) आवेदन अनुमोदित किया गया है।

(v) इलैक्ट्रॉनिक संघटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (स्पेक्स)

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए अक्षमता को दूर करने में मदद करने के लिए 1 अप्रैल 2020 को स्पेक्स को अधिसूचित किया गया था। इस योजना ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25 % का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया, जिसमें डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला शामिल है। इस योजना के तहत लक्षित खंड इलेक्ट्रॉनिक घटक, एटीएमपी, पूंजीगत सामान, ई-अपशिष्ट और सौर मूल्य श्रृंखला हैं। आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत दो (02) आवेदन, तिरुपति और चित्तूर में एक-एक आवेदन अनुमोदित किए गए हैं।

(vi) संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स)

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय में निवेश के लिए सब्सिडी प्रदान की गई (एसईजेड इकाइयों में स्थापित इकाइयों के लिए 20% और गैर-एसईजेड इकाइयों के लिए 25%)। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, मोबाइल फोन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पीसीबीए और रक्षा, चिकित्सा, औद्योगिक, ऊर्जा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए चित्तूर में छह (06) और तिरुपति, कृष्णा और विशाखापत्तनम जिलों में एक-एक (01) के साथ कुल नौ (09) आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान एवं विकास और कौशल पहलें

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0)

सेटअप समय को कम करने और उत्पादन दक्षता बढ़ाने के लिए तैयार भूमि, उपयोगिताओं और सामान्य सुविधाओं के साथ प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण अवसरंचना प्रदान करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अधिसूचित किया। इन क्लस्टरों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभिन्न केन्द्र-राज्य वित्तीय सहायता मॉडलों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारें अपेक्षित अवसंरचना के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती हैं। चित्तूर जिले में 380 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ तीन (03) ईएमसी को मंजूरी दी गई है, जो 163 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 708 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हैं। इसी तरह, वाईएसआर कडप्पा जिले में ईएमसी 2.0 के तहत एक (01) क्लस्टर को 749 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ मंजूरी दी गई है, जो 350 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्त सहायता के साथ 540 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है।

चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम

सरकार ने चिप डिजाइन में उद्योग के लिए तैयार जनशक्ति प्रदान करने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत, अत्याधुनिक चिप डिजाइन टूल्स तक पहुंच बिना किसी लागत के प्रदान की गई है। अब तक, आन्ध्र प्रदेश में तेईस (23) शैक्षिक संस्थाओं को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन स्वचालन (ईडीए) उपकरणों तक पहुंच प्रदान की गई है, जिनमें से चार (04)

तिरुपति में, दो (02) कुरनूल में और एक-एक (01) रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुर और नान्याल जिले में हैं। उपर्युक्त के अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है:

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तिरुपति
2. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटी-डीएम), कुरनूल
3. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पश्चिम गोदावरी
4. श्री विष्णु इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वुमन, भीमावरम, पश्चिम गोदावरी

<u>कौशल</u>

आंध्र प्रदेश में नाइलिट तिरुपति केंद्र की स्थापना नवीन पाठ्यक्रम विकास, उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण और उभरती प्रौद्योगिकियों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से आईईसीटी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए की गई है। केंद्र एक कुशल कार्यबल के विकास का समर्थन करके और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन इकोसिस्टम को सुदृढ़ करके भारत सेमीकंडक्टर मिशन में भी योगदान देगा।

नाइलिट तिरुपति के लिए वीएलएसआई/सेमीकंडक्टर डोमेन के तहत प्रशिक्षण लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

कार्यक्रम का प्रकार	**प्रशिक्षण लक्ष्य**
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	60
अल्पकालिक पाठ्यक्रम	270
उद्योग के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम	60
संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)	60
वीएलएसआई/सेमीकंडक्टर डोमेन में कुल प्रतिभागी	**450**

इन पहलों को उद्योग-प्रासंगिक कौशल को बढ़ाकर, अकादमिक-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के उद्देश्यों का समर्थन करके सेमीकंडक्टर प्रतिभा पाइपलाइन को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में, नाइलिट का तिरुपति में एक केंद्र और राज्य भर में 20+ भागीदार संस्थान हैं, जिनमें से 7 रायलसीमा क्षेत्र में हैं।

*****